जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 94 प्रभात बीकानेर, मंगलवार, 28 अक्टूबर, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

अमेरिका के विदेश सचिव रूबियो ने ढूँढ कर एस. जयशंकर से मुलाकात की और बहुत मीठी-मीठी बातें कीं

रूबियो के इस प्रयास से भारत का विदेश मंत्रालय अचंभित, पर खुश भी है

- रूबियो ने अपनी मीठी बातों से ट्रंप की तल्खियों को बैलेंस करने का प्रयास किया।
- भारत में यह धारणा जोर पकड़ती जा रही थी कि ट्रंप भारत से संबंधों को तत्कालिक आर्थिक लाभ के चश्मे से देखते हैं, न कि दीर्घकालिक स्थाई आर्थिक लाभ दृष्टि से।
- कुछ समय पूर्व तक 65 प्रतिशत भारतीय जनता अमेरिका से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहती थी जो 2023 में 50 प्रतिशत रह गई।
- भारत का विदेश मंत्रालय रूबियो के प्रयास से इसलिए भी प्रसन्न है, क्योंकि इस प्रयास से यह स्थापित हो गया कि वॉशिंगटन से भारत की मित्रता ऑटोमैटिक नहीं हैं, बल्कि यह रिश्ता भारत के आर्थिक हित व स्वायत्तता के आदर पर ही स्थापित हो सकता है।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। कुछ दिन पहले 48 वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान कुआलालंपुर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से हुई मुलाकात ने कूटनीतिक हलकों से कहीं आगे तक ध्यान खींचा है। यह भेंट भले ही एक शिष्टाचार भेंट प्रतीत होती है, लेकिन इसके पीछे यह गहरा संदेश छिपा है कि डॉनल्ड ट्रंप की तीखी बयानबाजी और टैरिफ की धमकियों के बावजूद, वाशिंगटन नई दिल्ली को एक रणनीतिक साझेदार के रुप में महत्व देता है। भारत के लिए, यह मुलाकात इरादों की परीक्षा थी: क्या ट्रंप का अमेरिका अब भी एक विश्वसनीय मित्र है, या फिर हितों को तोलने वाला लेन-देन आधारित साझेदार?

एक प्रमुख रिपब्लिकन नेता और ट्रंप के सबसे करीबी सीनेट सहयोगियों में से एक, रुबियो, चीन के खिलाफ सख़्त रुख और इण्डो- पैसिफिक साझेदारी को मजबूत करने के समर्थक रहे हैं। जयशंकर के साथ उनकी यह भेंट, शांत कूटनीति, ट्रंप की आक्रामक शैली और संस्थागत स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश थी। भारत के लिए द्विदलीय समर्थन को रेखांकित करके, रुबियो का उद्देश्य था, इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिका द्वारा भारतीय इस्पात और दवा कंपनियों पर नए टैरिफ लगाए जाने के बाद नई दिल्ली के नीतिगत हलकों में उभरी आशंकाओं को शांत करना।

समय महत्वपूर्ण था। भारत में जनता की भावना, जो कभी अमेरिका के प्रति अत्यधिक सकारात्मक थी, अब फिसलने लगी है। सर्वेक्षणों के अनुसार, 2023 में जहाँ 65 प्रतिशत भारतीय अमेरिका के प्रति सकारात्मक रुख रखते थे, वहीं 2025 के मध्य में यह आंकड़ा बमुश्किल 50 प्रतिशत रह गया और यह धारणा बढ़ती जा रही है कि वाशिंगटन का "अमेरिका फ़र्स्ट" व्यापार एजेंडा भारत जैसे साझेदारों को दरकिनार कर रहा है। व्यापक चिंता यह है कि ट्रम्प 2.0 में अमेरिका अपने सहयोगियों को दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास के बजाय, मुख्य रूप से अल्पकालिक आर्थिक लाभ के नज़रिए से देख रहा है।

इस प्रकार, रुबियो का हस्तक्षेप इसलिए भी अहम था, क्योंकि उन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी के स्तंभों-प्रौद्योगिकी सहयोग, रक्षा सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों को दोहराया। उन्होंने कथित तौर पर सेमीकंडक्टर निवेश के विस्तार, संयुक्त रक्षा उत्पादन और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा की, जो ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग में चीन के विकल्प के रूप में उभरने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप हैं। नई दिल्ली के लिए, ये प्रतिबद्धताएँ मायने रखती हैं: ये संकेत देती हैं कि अमेरिका के साथ संबंध सिर्फ़ एक बैलेंस-शीट गणना से कहीं बढ़कर हैं।

फिर भी, ये प्रतीकात्मकता इस विषमता को छिपा नहीं सकती। हालाँकि अमेरिका अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति में भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है, फिर भी उसने व्यापार बाधाओं, डेटा स्थानीयकरण और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्वदेशी सर्वेक्षण पोत नौसेना में शामिल होगा

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर। देश में ही निर्मित सर्वेक्षण पोत इक्षक को अगले महीने कोच्चि नौसैनिक बेस में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जायेगा। नौसेना के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि इस पोत को 6 नवम्बर को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में नौसेना में शामिल किया जायेगा।

इक्षक नौसेना में शामिल किये जाने वाला अपनी श्रेणी का तीसरा पोत है और यह उन्नत, अत्याधुनिक प्लेटफार्मों के

- कोच्चि नौसेना बेस पर नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में 6 नवम्बर को 'इक्षक' को बेडे में शामिल किया जायेगा।

निर्माण के प्रति नौसेना की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। साथ ही इससे क्षमता संवर्धन और आत्मनिर्भरता की गति को आगे बढ़ ाते हुए स्वदेशी जल सर्वेक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता में एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड, कोलकाता द्वारा निर्मित पोत इक्षक में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह पोत जीआरएसई और भारतीय एमएसएमई के बीच सफल सहयोग का प्रमाण है, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना और शक्ति को गर्व से दर्शाता है।

जल सर्वेक्षण कार्यों की प्राथमिक भूमिका के अलावा इसे दोहरी भूमिका

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अगर जनरल लड़ाई छोड़ भागे तो सेना कब तक टिकी रह सकती है?'

प्रशांत किशोर की स्वयं चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद उनकी पार्टी साइड लाइन्ड सी हो गई है बिहार चुनावों में

- शायद यह भांपते हुए, प्रशांत किशोर ने यह टिप्पणी की है कि चुनाव के बाद या तो वे अर्श पे होंगे या फिर फर्श पर।
- कांग्रेस भी कुछ नाखुश सी लगती है, तभी पटना में मंगलवार को तेजस्वी यादव द्वारा जारी होने वाले महागठबंधन के घोषणा पत्र के समारोह में न तो राहुल गांधी होंगे और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे।
- भाजपा भी कुछ मायूस सी है कि अब तक प्रधानमंत्री के पूरे शासनकाल में पार्टी अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनवा सकी।
- भाजपा को आशा है कि इस बार उसकी इस आकांक्षा की पूर्ति होगी।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। भारी उतार चढ़ाव का सामना कर रहे बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार जोरों पर है और चुनावों में सीधे मुकाबले के आसार प्रबल हो रहे हैं। तेज़ी से हो रही उथल-पुथल एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर की ओर बढ़ रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रशांत किशोर का बहुचर्चित तीसरा पहिया धीरे-धीरे हाशिये पर जा रहा है।

माना जा रहा है कि जिस दिन प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव न लड़ने की घोषणा की, उसी दिन उनका चुनावी दांव उल्टा पड़ गया। इसके बाद यह आरोप लगने लगे कि अगर जनरल मैदान छोड़ दें, तो क्या सेना उनके पीछे आ सकती है?

प्रशांत किशोर पहले ही कह चुके थे कि या तो वह पहले होंगे या आखिरी। अर्श पे या फ़र्श पे।

महागठबंधन का चुनावी घोषणापत्र कल जारी होगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव के साथ न तो राहुल गांधी और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद होंगे। राहुल गांधी के खास माने जाने वाले के.सी. वेणुगोपाल पटना में हैं और उनके पार्टी का प्रतिनिधित्व करने की संभावना है।

राहुल गांधी 28 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के साथ बिहार में तीन जनसभाएँ करेंगे और उसके बाद प्रियंका गांधी के साथ राहुल की सभा के लिए कुछ और दिन निर्धारित किए गए हैं।

चुनाव के बाद अगर महागठबंधन सत्ता में आता है, तो कांग्रेस का एक उपमुख्यमंत्री होगा, लेकिन इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। वे सहनी को उपमुख्यमंत्री बनाने पर इसलिए सहमत हुए क्योंकि वे कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार थे। सहनी की वीआईपी पार्टी का कई इलाकों में अच्छा-खासा प्रभाव है और उनके गठबंधन में शामिल होने से महागठबंधन को फायदा होने की संभावना है।

भाजपा ने मुख्यमंत्रियों, केन्द्रीय मंत्रियों और अन्य लोगों को बिहार में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आखिर बिहार चुनाव प्रचार से क्यों दूर हैं राहुल

राहुल ने आखिरी बार एक सितम्बर को बिहार में सभा की थी, उसके बाद से वे बिहार नहीं गए हैं

- यहाँ तक कि महागठबंधन का घोषणा पत्र मंगलवार को जारी किया जा रहा है, पर, उसमें भी राहुल उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
- चर्चा है कि राहुल एक तो प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टी लालू यादव से सीटों के लिए सही तरीके से सौदेबाजी नहीं कर पाई।
- इसके अलावा तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किए जाने के कारण, राहुल बिहार में दूसरे दर्जे की भूमिका निभाना नहीं चाहते हैं।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। राहुल गांधी को बिहार में आखिरी बार 1 सितम्बर को देखा गया था, जब उन्होंने अपनी 'वोटर अधिकार यात्रा' की समापन रैली को संबोधित किया था। इसलिए सवाल यह उठता है कि आखिर क्या कारण है कि वे चुनावी राज्य बिहार में इतने लंबे समय से अनुपस्थित हैं? क्या उनका अनुपस्थित रहना महागठबंधन की इस रणनीति का हिस्सा है, कि राहुल बनाम मोदी का मुद्दा मुख्य रुप से सामने न आए? क्या इसका कारण यह है कि राहुल राज्य पार्टी नेतृत्व से नाखुश हैं, क्योंकि वह आरजेडी के साथ सीटों के बंटवारे पर दृढ़ता नहीं दिखा सका? या फिर क्या ऐसा इसलिए है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रुप में नामित किए जाने के बाद, वह नहीं चाहते कि उन्हें आरजेडी नेता के सामने दूसरे नम्बर के नेता के रुप में देखा जाए?

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के कई अन्य नेता जल्द ही बिहार का दौरा करेंगे और 6 नवम्बर को प्रचार अभियान के समापन से कुछ दिन पहले एक जोरदार प्रचार करेंगे। संकेत मिल रहे हैं कि राहुल 2 नवम्बर को बिहार पहुंचेंगे और पहले चरण में खगड़िया और सीमांचल क्षेत्र के अन्य स्थानों पर रैलियों को संबोधित करेंगे। हालांकि, सवाल यह भी है कि कांग्रेस के लिए यह बहुत देर से की गई कोशिश तो साबित नहीं होगी?

शीर्ष भाजपा नेताओं में नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पहले ही प्रचार में जुट चुके हैं, और यहां

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री ने छठ पूजा की शुभकामनायें दी

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को देशवासियों को छठ पूजा के पहले अर्ध्य के मौके पर शुभकामनाएं दीं।

मोदी ने इस अवसर पर अपने एक्स पोस्ट पर कविता पोडवाल द्वारा

- उन्होंने कविता पोडवाल का छठी मैया का भक्ति गीत एक्स पोस्ट पर साझा किया।

गाया हुआ छठी मैया को समर्पित भक्ति गीत भी साझा किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा, "देश भर के अपने परिवारजनों को महापर्व छठ के संध्या अर्ध्य की अनंत शुभकामनाएं।

इस पावन अवसर पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्ध्य अर्पित करने की हमारी परंपरा बहुत विशिष्ट है।

सूर्यदेव की कृपा से सबका कल्याण हो, सबको जीवन में सुख-संपदा और सफलता की प्राप्ति हो, यही कामना है। जय छठी मइया!"

भारत-अमेरिका ट्रेड वार्ता ब्रेकथ्रू निर्णायक दौर में पहुँची

ट्रंप द्वारा रूस की ऑयल कंपनियों से कारोबार करने वाले बैंकों को प्रतिबंधित करने से धीरे-धीरे सभी देशों ने अन्यत्र रास्ता खोज लिया

- भारत ने भी मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिकी कंपनियों से तेल खरीद शुरु कर दी, जिससे अमेरिका ने भारत पर लगाये रेसिप्रोकल टैरिफ हटाने का इरादा दिखाया।
- इस घटनाक्रम से भारत-अमेरिका ट्रेड, लाईन पर आना शुरु हो गया है।
- भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कलकत्ता में पत्रकारों से बात करते हुए संकेत दिए।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब हैं। इस समझौते के तहत, भारत से अमेरिका जाने वाले निर्यात पर लगाए गए "रैसिप्रोकल टैरिफ" हटाए जा सकते हैं।

रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर लगाए गए भेदभावपूर्ण शुल्क को भी इस दौर की व्यापार वार्ता में शामिल किया गया है और संभावना है कि इसे भी वापस लिया जा सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर एक विशेष दंडात्मक शुल्क लगाया था। उन्होंने रूस के साथ ऐसे तेल व्यापार में लेन-देन की सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों और वित्तीय कंपनियों पर भी अतिरिक्त प्रतिबंधों की घोषणा की थी।

इन प्रतिबंधों के बाद, अधिकांश बैंकों ने रूसी तेल कंपनियों के साथ किसी भी तरह के लेन-देन से परहेज़ करना शुरु कर दिया है। ट्रंप ने अपने ताज़ा आदेशों के तहत, रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों, रोसनेफ्ट और लुकोइल पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिए हैं।

कई भारतीय कंपनियाँ कथित तौर पर अब मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिकी और अमेरिकी कंपनियों से तेल खरीदने पर विचार कर रही हैं, जो रूसी तेल कंपनियों के साथ अपने खरीद समझौते समाप्त कर रही हैं। एक बार जब ये कंपनियाँ रूसी तेल खरीद से दूर हो जाएँगी, तो विशेष दंडात्मक शुल्क हटाया जा सकता है।

यह घटनाक्रम अमेरिका के साथ एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंध, नए सिरे से तय किये जाएं, जैसा कि उसने अन्य देशों के साथ किये थे।

भारत ने व्यापार वार्ता शुरु तो की थी, लेकिन उसने अमेरिकी माँगों के आगे घुटने नहीं टेके और अपने व्यापारिक हितों पर डटा रहा। इसके परिणामस्वरूप, अमेरिकी राष्ट्रपति ने मनमाने ढंग से "भारतीय निर्यात पर रैसिप्रोकल टैरिफ" लगा दिए।

अब तक दोनों देशों के बीच पाँच दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, ताकि मतभेद दूर कर एक "फ्रेमवर्क एग्रीमेंट" (रूपरेखा समझौता) तैयार किया जा सके। लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों देशों के विचार कई मुद्दों पर अलग-अलग थे, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में बाज़ार तक पहुँच को लेकर।

जहाँ अमेरिका ने अपने कृषि उत्पादों के लिए अधिक पहुँच की माँग की थी, वहीं भारत ने भारतीय किसानों, खासकर छोटे किसानों, की चिंता के कारण अमेरिकी अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा, दवाओं और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीजेआई गवई पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वकील राकेश किशोर के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के

- सुप्रीम कोर्ट ने जूता फेंकने क आरोपी राकेश किशोर के खिलाफ अपराधिक अवमानना की कार्यवाही से इन्कार कर दिया, क्योंकि सीजेआई गवई ने राकेश किशोर को माफ कर दिया है।

खिलाफ अभद्र व्यवहार के मामले में अपराधी अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से भेंट के बाद राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ीं

यह माना जा रहा है कि 2028 के चुनावों की रणनीति बनाने के लिए संगठन व सरकार में व्यापक फेरबदल हो सकता है

जयपुर, 27 अक्टूबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार सुबह विशेष विमान से अचानक दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे दीवाली के बाद की शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को लेकर काफी चर्चा हो रही है।

सूत्रों के अनुसार, इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और सरकार के कामकाज को लेकर विस्तृत वार्ता हुई। राज्य में पिछले 22 महीनों से सीमित मंत्रियों के साथ सरकार चल रही है, जिससे कई विभागों का कार्यभार बढ़ा हुआ है और प्रशासनिक निर्णयों में देरी भी सामने आ रही है। इसलिए अब जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना और मजबूत मानी जा रही है।

बताया गया कि मुखमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश के विकास कार्यों की जानकारी दी और प्रशासनिक चुनौतियों से भी अवगत कराया। इसके साथ ही 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले पहले राजस्थानी प्रवासी दिवस का निमंत्रण भी दिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और प्रदेश के विकास कार्यों की जानकारी दी व प्रशासनिक चुनौतियों से भी अवगत कराया।

- मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से तीन माह में तीसरी मुलाकात है। वे पहले जुलाई और सितम्बर में भी प्रधानमंत्री से मिले थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री से यह तीन महीनों में तीसरी मुलाकात है। इससे पहले वे जुलाई और सितंबर में भी पीएम मोदी से मिल चुके हैं। लगातार हो रही इन मुलाकातों को लेकर यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि संगठनात्मक स्तर पर भी बड़ा बदलाव हो सकता है।

प्रदेश भाजपा में कई पद लंबे समय से खाली हैं और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी देरी हो रही है। ऐसे में पार्टी के भीतर संतुलन साधते हुए सभी गुटों को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस शासन के बाद मिले बड़े जनादेश को मजबूत दिशा देने और 2028 के विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाने के लिए भाजपा संगठन और सरकार में व्यापक फेरबदल हो सकती है।

दिवाली बाद के समय को शुभ समय मानते हुए प्रदेश की राजनीति में अब बड़े फैसलों की राह खुलती दिख रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दी गई अपनी रिपोर्ट में विकास कार्यों की गति और तेज करने की इच्छा जताई है, ताकि जनता के भरोसे पर खरा उतरा जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्री शर्मा को जनसेवा के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अब इस मुलाकात के बाद पूरे प्रदेश की निगाह मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख और नए चेहरों की सूची पर टिकी है।

राम मंदिर परिसर के सभी 15 मंदिरों का निर्माण पूरा

अयोध्या, 27 अक्टूबर। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य मंदिर समेत परकोटे के छह मंदिरों (शिव, गणेश, हनुमान, सूर्य, मां भगवती, मां अन्नपूर्णा और शेषावतार मंदिर) का निर्माण पूरा हो गया है। साथ ही, इन सभी पर

- श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह जानकारी दी व कहा कि ध्वजारोहण समारोह के बाद श्रद्धालु सभी मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे।

ध्वजदंड और कलश भी स्थापित कर दिये गये हैं। परिसर के सभी 15 मंदिर अब पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। यह जानकारी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)